

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 34/2016-

अपीलांत-

शेरखां पुत्र भाईखां जाति
मुसलमान निवासी दुर्गापुरा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट्स -

1. तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर
2. नूरखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान
निवासी दुर्गापुरा तहसील पचपदरा जिला
बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश दिनांक 10.04.2015 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा
अपीलांत व उत्तरदाता सं. 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को
विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मेघाराम चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

1. अपीलांत की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा दुर्गापुरा के खसरा नंबर 238, 291, 292, 296 व 326 रकबा क्रमशः 17-18, 00-04, 46-05, 42-06, 02-02 बीघा भूमि के खातेदारान नूरखां, शेरखां पि० भाईखां कौम मुसलमान साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2015 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले जमान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का बागावास द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी



विश्राम मीणा
बाड़मेर

मौजा दुर्गापुरा के खाता संख्या 101 का मैंने मौके पर सहखातेदारों के साथ जाकर उनको अपने बंट में आई हुई भूमि को नापकर बता दी है। जिस पर वो काबिज हो गए हैं तथा सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भलीभांति अवगत करा दिया है। बंटवाडे से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है और न ही जोडा गया है, रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1201 दिनांक 10.04.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2015 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं। विवादित आराजी के खसरा नंबर 238 में जिस स्थान पर पूर्व बाहामी बंटवाडा अनुसार 30-40 वर्षों से अपीलांट का कब्जा एवं काश्त स्थापित है उस भूमि को अपीलाधीन विभाजन द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी एवं जिस स्थान पर रेस्पोंडेंट संख्या 2 का कब्जा था वह भूमि अपीलांट के नाम दर्ज कर दी। अपीलांट अनपढ व्यक्ति है जिसे पढना-लिखना नहीं आता है जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 2 सहित उसका पुत्र सतार खां पढे-लिखे एवं किराणे के बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने हलका पटवारी से मिलकर विवादित आराजी के पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा से भिन्न गलत तथ्य एवं दस्तावेज तैयार कर अपीलांट से धोखे में अंगूठा लगवा लिया। रेस्पोंडेंट ने विवादित आराजी 5 खसरा में से एक ही स्थान पर खसरा नंबर 238, 292 व 296 में अच्छी जमीन ली है एवं अपीलांट को पांच भागों में भूमि दी है इसके साथ ही अपीलांट के कब्जे





विद्वान् कृतवन्त
बाइपेर

काश्त की भूमि जो हाईवे पर स्थित थी, को रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपने हिस्से में ले ली। इस प्रकार रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने राजस्व अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर अपने असम्यक असर के द्वारा अपीलाधीन विभाजन पारित करवा दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 10.04.2015 की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम भी कर दी जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई परन्तु वर्तमान में अर्सा 15 दिन पूर्व जब रेस्पोंडेंट सं. 2 ने अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़े के अनुसार हाईवे पर दी गई भूमि पर कब्जा हटाने का कहा, जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो रेस्पोंडेंट ने बताया कि आपके कब्जे-काश्त वाली भूमि बंटवाड़े में हमें प्राप्त हुई है तथा आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा, वरना हमें मजबूर होकर आपको जबरन बेदखल करना पड़ेगा। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 20.06.2015 को प्राप्त हुई तथा सम्यक् तत्परता के साथ यह अपील पेश की गई है, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी का नये सिरे से विभाजन किये जाने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोंडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 2 नूरखां ने तहसीलदार पचपदरा के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु प्रार्थना-पत्र एवं विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान के हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन एवं कब्जा-काश्त की ताईद करते हुए समान लगान का विभाजन होने के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई। इस पर पक्षकारान की स्वतंत्र सहमति के आधार पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि का विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राजात हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में उसकी स्वतंत्र सहमति पर पारित किया गया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रतिकूल कथन करने से विबंधित हैं। एक बार राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी स्वतंत्र सहमति व्यक्त करने के बाद उसके विरुद्ध प्रतिकूल कथन करने से बाधित हैं तथा सहमति से किये गये विभाजन के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलांट द्वारा पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाड़े एवं मौके-कब्जे के




खिलात कलक्टर
शेरखां

अनुसार विभाजन स्वीकार करने के पश्चात अब उसकी नीयत में खोटा आ गया है तथा रेस्पोंडेंट द्वारा विकसित की गई भूमि को हड़पने एवं रेस्पोंडेंट को खर्चे से जैरबार करने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई है जो सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, लिहाजा अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा दुर्गापुरा के खसरा नंबर 238, 291, 292, 296 व 326 रकबा क्रमशः 17-18, 00-04, 46-05, 42-06, 02-02 बीघा भूमि के खातेदारान नूरखां, शेरखां पि० भाईखां कौम मुसलमान साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2015 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बागावास द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा दुर्गापुरा के खाता संख्या 101 का मैंने मौके पर सहखातेदारों के साथ जाकर उनको अपने बंट में आई हुई भूमि को नापकर बता दी है। जिस पर वो काबिज हो गए हैं तथा सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भलीभांति अवगत करा दिया है। बंटवाडे से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है और न ही जोड़ा गया है, रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1201 दिनांक 10.04.2015 पारित किया गया। अपीलांत के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश उसे धोखे में रखकर अंगुष्ठ निशान लेकर जारी किया गया है। अपीलांत के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलाधीन विभाजन के द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 2 ने अपने हिस्से की भूमि सड़क पर ली गई है जबकि अपीलांत का पूर्व बाहामी बंटवाडा अनुसार सड़क पर कब्जा काश्त बराबर था। इसके अलावा यह भी कथन है कि रेस्पोंडेंट ने अपने हिस्से में आने वाल भूमि एक ही स्थान पर ले ली जबकि अपीलांत को पांच टुकड़ों में देते हुए सड़क पर भूमि कम दी गई है। इस संबंध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के संलग्न विभाजन नक्शा का अवलोकन से पाया जाता है कि रेस्पोंडेंट सं. 2 को उसके हिस्से में आने




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

वाली भूमि एक ही स्थान पर एकल चक में सड़क पर दी गई हैं जबकि अपीलांट को तीन टुकड़ों में जिसमें एक हिस्सा सड़क के दोनों तरफ तथा दूसरा हिस्सा सड़क पर दूरी पर दिया गया हैं एवं यह हिस्सा अत्यंत छोटा होने से अपीलांट के लिये अनुपयोगी प्रतीत होता है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या उक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 में यथा विहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। राजस्व नियमावली के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में भूमि की किस्म एवं अवस्थिति को मध्य नजर रखा जाना आवश्यक हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के हिस्से में आने वाली भूमि को तीन टुकड़ों में विभक्त किया गया है तथा इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट के हिस्से में आये एक छोटे से भाग को उसके मूल बड़े भाग से दूर रखा गया हैं जिससे उसे आने-जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि मौके पर बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़े से भिन्न अपीलाधीन विभाजन होने से अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रेस्पो0 के हिस्से में चली गयी हैं। इस प्रकार तहसीलदार पचपदरा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में अंकित कर दी है तथा रास्ता का प्रावधान भी समुचित रूप से नहीं किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे-काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 10.04.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति




 जिला कलेक्टर
 बाड़मेर

अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर